CEDSI TIMES

Your Skilling Partner...

मदर डेयरी पश्चिम बंगाल में मूल्य वर्धित सेगमेंट का विस्तार करेगी, 5 साल में पूर्व से 500 करोड़ रुपये का कारोबार करेगी

राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी मदर डेयरी फ्रूट एंड वेजिटेबल प्राइवेट लिमिटेड ने कहा कि वह अगले पांच वर्षों में पश्चिम बंगाल में विस्तार करने के लिए तैयार है, जिससे मूल्य वर्धित डेयरी उत्पादों की विनिर्माण क्षमता में वृद्धि होगी और वह अधिक जिलों तक पहुंच सकेगा।

आइसक्रीम, दही और मक्खन सहित कंपनी के मूल्य वर्धित डेयरी उत्पाद वर्तमान में राज्य के 10 जिलों में उपलब्ध हैं और इसका लक्ष्य पांच वर्षों के भीतर गिनती को दोगुना करके 20 जिलों तक पहुंचना है।

शर्मा ने कहा कि कंपनी का लक्ष्य अगले पांच वर्षों में 30,000 से अधिक आउटलेट्स करना है जो वर्तमान में लगभग 17,000 है।

गोवा डेयरी कर्नाटक से गाय का दूध लेने की योजना बना रही है

गोवा डेयरी अपनी दैनिक मांग को पूरा करने के लिए कर्नाटक से गाय का दूध खरीदने पर विचार कर रही है। 2012 से पहले गोवा डेयरी को महाराष्ट्र और कर्नाटक से दूध मिलता था क्योंकि स्थानीय आपूर्ति पर्याप्त नहीं थी। गोवा डेयरी अब ऐसी ही स्थिति का सामना कर रही है।

डेयरी ने एक पखवाड़े से गोवा के खुदरा बाजार में फुल क्रीम (हाई फैट) दूध की आपूर्ति बंद कर दी है। डेयरी के विशेष कर्तव्य अधिकारी (ओएसडी) काशी डी नाइक ने कहा कि वे दूध की बिक्री का जोखिम नहीं उठा सकते क्योंकि आपूर्तिकर्ता ने कीमत बढ़ा दी है।

नाइक ने कहा कि आमतौर पर दुग्ध उत्पादन में कमी आती है जो जुलाई तक जारी रहती है और उसके बाद फ्लश सीजन में उत्पादन बढ़ेगा। नाइक ने कहा, "कम से कम इस सीजन के लिए, हम अपनी दैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए कर्नाटक मिल्क फेडरेशन से गाय का दूध खरीदने की योजना बना रहे हैं।"

परियोजना गिर वाराणसी उत्तर प्रदेश में 'श्वेत क्रांति' की शुरुआत करने के लिए

उत्तर प्रदेश में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ, रामनगर में "प्रोजेक्ट गिर, वाराणसी" शुरू किया गया था। परियोजना का लाभ दुधारू पशुओं के मालिकों, विशेषकर छोटे और सीमांत किसानों को मिलेगा।

पशुपालन और डेयरी विभाग (डीएएचडी) ने 36.5 करोड़ रुपये के प्रावधान के साथ वाराणसी में अगले पांच वर्षों के लिए गिर परियोजना को लागू करने की योजना बनाई है।

राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत, 450 गिर गायें को जल्द ही लाभार्थी किसानों को वितरित किया जा रहा है । ये वह गायें है जिन्हें पहले ही गिर गायों (गुजरात में सौराष्ट्र) के प्रजनन पथ से शामिल किया जा चुका है । एनडीडीबी उच्च आनुवंशिक योग्यता वाली गायों और सर्वश्रेष्ठ पुरुषों के वीर्य का उपयोग करके उत्पादित आईवीएफ भ्रूण का उपयोग करके 5,000 गर्भधारण की स्थापना करेगा।

डेयरी क्षेत्र को निर्यात में सुधार पर ध्यान देना चाहिए: अमित शाह

केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने डेयरी क्षेत्र को निर्यात में सुधार पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित किया। "सहकारिता आंदोलन ने भारत को आत्मनिर्भर बनाया है। इसने पोषण की समस्या को सफलतापूर्वक संबोधित किया है। भारत पहले से ही विश्व स्तर पर दूध का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता है, हालांकि, सहकारी समितियों का ध्यान अब चारा लागत और दूध उत्पादन लागत को कम करके डिजिटलीकरण द्वारा सुधार करने पर होना चाहिए। जब गुणवत्ता में सुधार होता है और उत्पादन लागत कम होती है, हम निर्यात बाजार को देख सकते हैं," उन्होंने अपने संबोधन के दौरान कहा। शाह ने डेयरी सहकारी समितियों को डिजिटलीकरण की ओर बढ़ने पर भी जोर दिया।

इसी तरह की राय व्यक्त करते हुए, आरबीआई के निदेशक, सतीश मराठे ने कहा, "भारत विश्व स्तर पर सबसे बड़े दूध उत्पादक के रूप में उभरा है और हमारी प्रति व्यक्ति खपत बढ़कर 400 ग्राम प्रति व्यक्ति हो गई है। यहां डेयरी सहकारी समितियों की बहुत बड़ी भूमिका है, कम्प्यूटरीकरण और डिजिटलीकरण अगला कदम है।"

मराठे ने आगे कहा, "भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) एक भुगतान गेटवे लेकर आया है, जो कई ग्रामीण संस्थानों को डिजिटल तरीके से सक्षम बनाएगा। यह वित्तीय सेवाओं के डिजिटलीकरण को और सक्षम करेगा और डेयरी सहकारी समितियों के अधिक वित्तीय समावेश को प्रोत्साहित करेगा।"

अमूल डेयरी का कहना है कि स्ट्रॉ बैन के कारण बिक्री में बाधा आ रही है

भारत ने पिछले हफ्ते छोटे रस और दूध पेय पैक के साथ पैक किए गए स्ट्रॉ पर आसन्न प्रतिबंध को माफ करने से इनकार कर दिया, जिससे $ 790 मिलियन उद्योग में भय पैदा हो गया।

अमूल डेयरी समूह ने कहा कि वह जुलाई से कुछ उत्पादों के लिए व्यवधान और उच्च इनपुट लागत के लिए तैयार है, जब प्लास्टिक स्ट्रॉ पर सरकार का प्रतिबंध लगा है। अमूल ने छोटे प्लास्टिक स्ट्रॉ को बदलने के लिए कोई व्यावहारिक समाधान नहीं निकाला है और पेपर संस्करण संभव नहीं है, अमूल के प्रबंध निदेशक आरएस सोढ़ी ने कहा।

प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी नदियों को चोक करने वाले प्रदूषणकारी, एकल-उपयोग वाले प्लास्टिक कचरे पर मुहर लगाने पर जोर दे रहे हैं। सरकार का मानना है कि छोटे स्ट्रॉ एक "कम उपयोगिता वाले उत्पाद" हैं और उन्हें पेपर स्ट्रॉ या टोंटी पाउच के लिए स्क्रैप किया जाना चाहिए।

सोढ़ी ने रॉयटर्स को बताया, "सरकार की मंशा अच्छी है (लेकिन) स्ट्रॉ कुल प्लास्टिक खपत का 0.1% भी नहीं है।" "पूरा उद्योग प्रभावित होगा।" सोढ़ी की टिप्पणी ऐसे समय में भारतीय पेय उद्योग में बढ़ते तनाव को रेखांकित करती है जब गर्मी के मौसम में मांग बढ़ जाती है । प्रतिबंध के साथ, ऐसे पैक की आपूर्ति बाधित हो जाएगी और निर्माता अधिक महंगे पैकेजिंग समाधानों में स्थानांतरित हो सकते हैं जिससे लागत बढ़ जाती है । सोढ़ी ने कहा, अमूल हर साल ऐसे अरबों कार्टन पैक बेचता है।

आयात पर 3 दशक के प्रतिबंध के बाद श्रीलंका दूध के लिए भारत से मदद के लिए उम्मीद में

श्रीलंका, जो पहले भारतीय डेयरी खिलाड़ियों तक पहुंच की अनुमति देने का विरोध करता था, अब नई दिल्ली में डेयरी खिलाड़ियों और नीति निर्माताओं से अपने मौजूदा दूध संकट से निपटने में सहायता करने का अनुरोध कर रहा है।

एक गंभीर आर्थिक संकट के बीच, श्रीलंका आवश्यक वस्तुओं पर कम चल रहा है, जिनमें से अधिकांश दूध पाउडर सहित आयात किए जाते हैं। खुदरा बाजारों में कीमतें श्रीलंकाई रुपये 1,500-2,000 रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई हैं, जो प्रभावी रूप से उन्हें औसत व्यक्ति की पहुंच से बाहर कर रही हैं।

विशेष रूप से, 1990 के दशक के उत्तरार्ध में, श्रीलंका ने राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (NDDB) से दूर कर दिया, जिसने देश को अपनी डेयरी सहकारी संरचना विकसित करने में सहायता की थी।

अधिवक्ता और नीति विशेषज्ञ विजय सरदाना के अनुसार, जबकि भारत ने दवाओं जैसी दैनिक आवश्यकताओं के लिए श्रीलंका को $ 1 बिलियन की क्रेडिट लाइन का विस्तार किया है, "वे इस लाइन ऑफ क्रेडिट के माध्यम से डेयरी उत्पादों की खरीद की अनुमति देने के लिए वाणिज्य मंत्रालय और एनडीडीबी से संपर्क कर सकते हैं। " एनडीडीबी और न ही अमूल और न ही किसी अन्य डेयरियों को श्रीलंका से संभावित डेयरी उत्पाद की मांग के संबंध में भारतीय अधिकारियों से कोई संचार प्राप्त हुआ है।

डेयरी प्रमुख मिल्मा के कारोबार में 25% की वृद्धि

मिल्मा ने 2021-22 में अपने कारोबार में 25% की वृद्धि दर्ज की है। इसने अपने कारोबार को पिछले वर्ष के 3,388 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 4,300 करोड़ रुपये कर दिया। 2019-20 में मिल्मा का टर्नओवर 3,210 करोड़ रुपये रहा।

"पिछले दो साल वास्तव में कठिन रहे हैं क्योंकि कोविड -19 महामारी ने हर तरफ से संकट पैदा कर दिया है। लेकिन मिल्मा हजारों किसानों और वफादार ग्राहकों द्वारा नेटवर्क पर दोहराए गए अडिग विश्वास पर खरा उतरने में सक्षम है, "मिल्मा के अध्यक्ष के. एस. मणि ने कहा।

उन्होंने कहा कि मिल्मा ने अपने तीन क्षेत्रीय संघों के साथ, महामारी द्वारा लगाए गए गंभीर बाधाओं के बावजूद पिछले दो वर्षों में खरीद, वितरण, कारोबार और लाभ में सर्वकालिक वृद्धि हासिल की है। 2021-22 में, मिल्मा ने किसानों को पशु चारा सब्सिडी और छूट के माध्यम से 7.95 करोड़ रुपये का लाभ दिया था।

पहली बार मार्च 2022 में किसानों से खरीदे गए प्रत्येक लीटर दूध पर एक रुपये की दर से 4.2 करोड़ रुपये का अतिरिक्त दूध मूल्य प्रदान किया जा रहा है।

CEDSI

Centre of Excellence for Dairy Skills in India

Join Our Membership Drive and Get Benefits of

- Platform to interact with other members in the sector
- Networking opportunities with corporate leaders and government authorities
- Special costs of training in Skill India Certified Programmes
- Access to our Journal and Publications
- Expert advice in day-to-day operations and management of livestock /farm productions
- Free registration on the job portal and regular updates on job vacancies in the sector
- Recognize your organization with CEDSI Yearly Awards and Recognition
- Chance to reach across the board through advertising in our press releases, news and articles
- Consultative and advisory services to help members
- Consulting and advisory services to help members
- Periodic e-newsletter for the latest news, govt. announcement and schemes in dairy sectors
- Updates on training programs of CEDSI and access to the training calendar

Who Can Become a Member -

Corporates/ Cooperatives

NGO's/CSR Foundations

Dairy Farmers

Students

Professional

www.cedsi.in

@cedsi_india